(ग) और (घ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकार को योजनावार दी जाती है न कि जिले-वार और इनका निष्पादन पूर्ण रूप से राज्य सरकार पर निर्भर करता है और इनको पूरा करने की निर्धारित तारीख, स्वीकृति की तारीख से 18 महीने बाद की होती है।

महानिदेशक, नागर विमानन के पास पंजीकृत विमान

349. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानिदेशक, नागर विमानन के पास कितने विमान पंजीकृत हैं जिन्हें राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है :

(ख) इनमें से कितने विमान मध्य प्रदेश के हैं और राज्य के नाम पंजीकृत विभिन्न प्रकार के विमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विमानों की उड्डयन योग्यता प्रमाणित करने के लिए भोपाल में कोई कार्यालय स्थापित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्टर में 906 विमान पंजीकृत हैं।

(ख) मध्य प्रदेश के पंजीकृत पते वाले 23 विमान हैं जिनमें से 19 का बेस राज्य के भीतर है और 4 का राज्य से बाहर। मध्य प्रदेश सरकार के नाम में पंजीकृत विमानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

विस्तृत	पंजीकरण संख्या
1. बी-200	वीटी–ईआईडी
2. डॉफिन हेलीकाप्टर	वीटी–ईएनडब्लू
3. चेतक हेलीकाप्टर	वीटी–ईसीई
4. चेतक हेलीकाप्टर	वीटी–ईधारडी

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान को उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र देने हेतु भोपाल में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है।

Recovery of penalty from Sohar India Airlines

350. SHRI G. Y. K.RISHNAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) the steps taken to recover Rs. 8 crores penalty imposed by the International Airports Authority of India on Sahara India Airlines for the damage caused to the Indira Gandhi International Airport property, due to the. recent crash of a Boeing 737 operated by Sahara; and

(b) the measures taken to prevent such incidents of crash by private air operator!.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GULAM NABI AZAD): (a) Initially a tentative claim of Rs. 8.00 crores was lodged by the International Airports Authority of India (IAAI) with M/s. Sahara India Airlines. However, bated on the factual de-tails, the low has been worked out to R«. 5.67 crore*. In order to reebver